संख्या-18/2023/I/368552/001-38-4002-99-3-2021

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-642/सम्प्रेक्षा/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0(अनु सं0-13)/23-24, दिनांक-03 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सामान्य वर्ग(अनुदान संख्या-13) की पात्रता श्रेणी में सम्मिलित आई0ए0पी0 के 3105+नॉन आई0ए0पी0 के 51959 = कुल 55064 आवास लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 22149.80 लाख वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राविधान से अनुदान संख्या-13 में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 में 2023-24 के लिये आई0ए0पी0 के 3105+नॉन आई0ए0पी0 के 51959 = कुल 55064 लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 22149.80 लाख (रूपये दो अरब इक्कीस करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक प्राविधान से अनुदान संख्या-13 के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/योजना के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रेत्तर किश्त धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(7) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(8) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि स्टेट नोडल बैंक एकाउन्ट से पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अन्तरित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-6/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक-02-02-2018, शासनादेश संख्या-04/2019/80/38-4-19-123(विविध)/2017, दिनांक-04-02-2019, शासनादेश संख्या-17/2019/248/38-4-19-123(विविध)/2017 टी.सी.-1, दिनांक-28-06-2019, शासनादेश संख्या-09/2021/150/38-4-21-123(विविध)/2017 टी.सी.-1, दिनांक-18-03-2021, शासनादेश संख्या-19/2021/240/38-4-21-123(विविध)/2017 टी.सी.-1, दिनांक 25-06-2021, शासनादेश संख्या-44/2021/671/38-4-2021-123(विविध)/2017, दिनांक 27-12-2021, शासनादेश संख्या-16/2022/225/38-4-22-123(विविध)/2017 टी.सी.-1, दिनांक-20-09-2022 एवं शासनादेश संख्या-11/2023/114/38-4-23-123(विविध)/2017 टी.सी.-1, दिनांक-11-04-2023 में विहित प्राविधानों के अधीन योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण में व्यय की जायेगी।

(12) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-06-मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-24-वृहत् निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स,

उप सचिव।

संख्या-18/2023/I/368552(1)/001-38-4002-99-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ,प्रयागराज)।
(5) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(6) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(10) श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, बजट, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड बुक।

राजीव कुमार वत्स,

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।